ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-8* November-2021
Anthology : The Research

भारतीय संघ व्यवस्था तथा राज्यपाल का पद

Indian Federal System and the Post of Governor

Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance: 23/11/2021, Date of Publication: 24/11//2021

गोमती चेलानी
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई
स्नातकोत्तर कन्या
महाविद्यालय, इंदौर,
मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों में सरकार के संसदीय स्वरूप की परिकल्पना की गई है। इसलिए संघ सरकार की तरह संसदीय ढांचे के अनुसार, राज्य सरकारों के भी कार्यपालिका के दो रूप हैं - संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक कार्यपालिका। हालांकि, संघ स्तर पर राष्ट्रपति के विपरीत, राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख जो कि राज्यपाल होता है, बड़े पैमाने पर औपचारिक कार्यों के अलावा भी केंद्र का प्रतिनिधित्व करने और संविधान की रक्षा करने का अधिकार रखता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसे पर्याप्त शक्तियों का एक दुर्जेय शस्त्रागार सौंपा गया है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका और उनकी शक्तियों और कार्यों के बारे में इस अस्पष्टता ने संघवाद और संघ-राज्य संबंधों की प्रकृति के संदर्भ में तीखी बहस और विवादों को जन्म दिया है।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि राज्यपालों ने कई बार तानाशाही की भूमिका निभाई है और सभी लोकतांत्रिक सीमाओं को पार किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने पक्षपातपूर्ण हितों के लिए अलग-अलग समय पर राज्यपाल की भूमिका का दुरुपयोग किया है, जिससे यह साबित होता है कि भारतीय समाज को अभी तक राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति की स्थिति हासिल नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के कार्यालय का राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग किया गया है और कुछ राज्यपालों ने अपने कार्यों द्वारा अपने पद की स्थिति को कम कर दिया है। ऐसा लगता है कि राज्यपाल केंद्र में सत्ताधारी दल के हाथ का औजार बन गया है। इसलिए, "भारतीय संघव्यवस्था तथा राज्यपाल का पद" शीर्षक वाला वर्तमान पत्र भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की शक्ति, कार्यों, वास्तविक स्थिति और राज्यपाल की नियुक्ति के तरीके से संबंधित कुछ प्रश्नों से संबंधित है। इस संबन्ध में सरकारिया आयोग के सुझावों और उनके क्रियान्वयन पर भी विचार किया गया है।

It is a well known fact that the Constitution of India envisages a parliamentary form of government at the centre as well as in the States. Therefore in accordance with the parliamentary framework like the union Government, the state Governments also have two forms of Executive — the constitutional head and the real executive. However unlike President at the Union level, the Constitutional head at the State level that is Governor in addition to largely ceremonial functions has also been empowered to represent the centre and to safeguard the constitution. For these purposes, he has been entrusted with a formidable armoury of powers. This ambiguity about the dual role of the Governor and his powers and functions has provoked sharp debates and controversies both in terms of nature of federalism and Union-state relations. It is a well known fact that the Governors have played a dictatorial role many a time and transcended all the democratic limits. Different political parties have misused the role of the Governor at different times for their partisan interests, thus proving that Indian society has yet to achieve the state of political modernisation and political culture. The office of Governor has been misused by the centre government for the political interest and some of the governors have abased the position of their office. It seems that the governor has become a tool in the hands of ruling party at centre. Therefore, the present paper entitled “Indian Federal System and the Post of Governor” deals with some questions related to the power, functions, actual position and the mode of appointment of the Governor in Indian democracy. The suggestions of Sarkariya commission and their implementation is also viewed.

मुख्य शब्द: राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भूमिका।

Key Words: Governor, Central Government, State Government, Role.

प्रस्तावना

राज्यपाल की नियुक्ति

संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है, "प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।" हालांकि, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति पांच साल के लिए होती है। लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत

अपना पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति उसे कभी भी वापस बुला सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारत में दो परंपराएँ रही हैं:

(i) राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के बाहर से की जाती है। लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जब इस अभिसमय का पालन नहीं किया गया था। एच.सी. मुकर्जी की नियुक्ति बंगाल में, 1956 में मैसूर में जे.सी. वेडियार बहादुर, 1966 में पंजाब में उज्जल सिंह और 1965 में जम्मू-कश्मीर में कर्ण सिंह ऐसे कुछ उदाहरण हैं। राज्य से किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करने की परंपरा का उद्देश्य राज्य की राजनीति में राज्यपाल की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

(ii) राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र द्वारा राज्यों से परामर्श किया जाता है। राज्यपाल की हर नियुक्ति में भी इस प्रथा का पालन नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में, राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी परामर्श नहीं किया गया था, उदाहरण के लिए मद्रास में श्री प्रकाश और उड़ीसा में कुमारस्वामी राय की नियुक्ति के मामले में। पंजाब में, मुख्यमंत्री गुरनाम सिंह ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित दो नामों को अस्वीकार कर दिया और कुछ नामों का सुझाव दिया, लेकिन केंद्र उनके नामों से सहमत नहीं था। बिहार में मुख्यमंत्री एम.पी. सिन्हा चाहते थे कि मौजूदा राज्यपाल एम.ए.अयंगर एक और कार्यकाल के लिए बने रहें लेकिन केंद्र ने एक नया राज्यपाल नियुक्त किया। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया था और नए राज्यपाल का स्वागत करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने उन्हें "अवांछित और अनभिनन्दनीय राज्यपाल" के रूप में वर्णित किया।

राज्यपालों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के एक अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि काफी संख्या में सेवानिवृत्त राजनेताओं को राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र के ये राजनेता जिनके साथ प्रधानमंत्री सहज नहीं हैं या चाहते हैं कि उन्हें सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया जाए, उन्हें भी राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। यहां तक कि सक्रिय राजनेताओं को भी पंजाब में अर्जुन सिंह की तरह राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब में अपने कार्यकाल के बाद, वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और सक्रिय राजनीति में बने रहे। हरिदेव जोशी का एक विशिष्ट उदाहरण है, जिन्होंने असम के राज्यपाल के अपने पद को त्याग दिया और अगले ही दिन उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा सेवानिवृत्त नौकरशाहों और न्यायाधीशों और सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे लोग राज्यपाल के पद की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं कर सकते। अक्सर राज्यपालों पर केंद्र में सत्ता पक्ष के हाथों में खेलने का आरोप लगाया जाता रहा है।[1]

राज्यपाल को हटाना

सामान्यतः राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाती है। इससे पहले, उसे वापस बुलाया जा सकता है या दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है या वह अपनी इच्छा से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। लेकिन ऐसे मामले भी आए हैं जब राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण बने रहे। दूसरी ओर राज्यपालों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले बर्खास्त कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में टी.एन.सिंह ने 1982 में राष्ट्रपति की खुशी पर इस्तीफा दे दिया। जनता दल और उसके सहयोगियों के सत्ता में आने के बाद, राज्यपालों के सामूहिक इस्तीफे की मांग की गई। अब, यह लगभग एक प्रथा बन गई है कि केंद्र में सरकार बदलने के साथ, ऐसे राज्यपाल, जो नई सरकार को पसंद नहीं हैं, बदल दिए जाते हैं। 1992 में, नागालैंड के राज्यपाल, एम.एम. थॉमस को राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया था और केंद्र से परामर्श किए बिना नए चुनाव का आदेश दिया था। 2001 में, तमिलनाडु की राज्यपाल फातिमा बीवी को वापस बुला लिया गया था क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार को राज्य में आंतरिक गड़बड़ी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि और दो केंद्रीय मंत्रियों को जयललिता सरकार ने गिरफ्तार किया था। यह आरोप लगाया गया था कि उसने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की तुलना में राज्य की सत्ताधारी पार्टी के एजेंट की तरह व्यवहार किया [2]।

राज्यपाल का स्थानांतरण

संविधान में राज्यपालों के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। हालांकि राज्यपालों का वैसे भी तबादला कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जी.डी. तपस्वी को यू.पी. से हरियाणा स्थानांतरित किया गया था। भागवत दयाल शर्मा का तबादला उड़ीसा से मध्य प्रदेश कर दिया गया। 1984 में, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने और केंद्र द्वारा वांछित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के राज्यपाल एपी शर्मा को पश्चिम बंगाल स्थानांतरित कर दिया गया।

राज्यपालों की नियुक्ति और हटाने के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा माहौल बनाया गया है जो राज्यपाल को केंद्र की लाइन पर चलने के लिए मजबूर करता है, अन्यथा उसे हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है।[3]

सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने के संबंध में निम्नलिखित सुझावों की सिफारिश की:

1. उसे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए।
2. वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।
3. वह एक अलग व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
4. वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने आम तौर पर और विशेष रूप से हाल के दिनों में राजनीति में बहुत अधिक भाग लिया हो।
5. यह वांछनीय है कि संघ में सत्तारूढ़ दल के एक राजनेता को उस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है जिसे किसी अन्य दल या अन्य दलों के संयोजन द्वारा चलाया जा रहा है।
6. राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के चयन में राज्य के मुख्यमंत्री के साथ प्रभावी परामर्श सुनिश्चित करने के लिए, परामर्श की प्रक्रिया संविधान में ही अनुच्छेद 155 में उपयुक्त रूप से संशोधन करके निर्धारित की जानी चाहिए।
7. भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष से राज्यपाल का चयन करने में प्रधान मंत्री द्वारा परामर्श किया जा सकता है। परामर्श गोपनीय और अनौपचारिक होना चाहिए और संवैधानिक दायित्व का विषय नहीं होना चाहिए।
8. किसी राज्य में राज्यपाल के पांच साल के कार्यकाल को बहुत ही कम और वह भी, किसी बेहद अनिवार्य कारण से बाधित नहीं किया जाना चाहिए।सिवाय जहां राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाएं कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा करना समीचीन नहीं है, जिस राज्यपाल का कार्यकाल पांच साल की सामान्य अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करने का प्रस्ताव है, उसे चाहिए प्रस्तावित कार्रवाई के आधारों से अनौपचारिक रूप से अवगत कराया जाए और इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। यह वांछनीय है कि राष्ट्रपति (वास्तव में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद) को राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाने के खिलाफ प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, भारत के उपराष्ट्रपति से मिलकर एक सलाहकार समूह द्वारा जांचा जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष या भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इस समूह की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, राष्ट्रपति मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।
9. जब, पांच साल की सामान्य शर्तों की समाप्ति से पहले, एक राज्यपाल इस्तीफा दे देता है या किसी अन्य राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक बयान दे सकती है जिसमें परिस्थितियों की व्याख्या की जा सकती है। कार्यकाल की समाप्ति। जहां किसी राज्यपाल को अपने कार्यकाल की समयपूर्व समाप्ति के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर दिया गया है, बयान में उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के जवाब में भी शामिल हो सकता है।
10. परंपरा के रूप में, राज्यपाल को अपना पद छोड़ने पर, राज्यपाल के रूप में दूसरे कार्यकाल या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव या चुनाव के अलावा, केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी अन्य नियुक्ति या लाभ के पद के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति। इस तरह के एक सम्मेलन में यह भी आवश्यक होना चाहिए कि, अपना पद छोड़ने या छोड़ने के बाद, राज्यपाल सक्रिय पक्षपातपूर्ण राजनीति में वापस नहीं आएगा।
11. राज्यपाल को अपने कार्यकाल के अंत में, चाहे उसकी अवधि कुछ भी हो, अपने और अपने जीवित पति या पत्नी के लिए उचित सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। [4]

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां

संविधान के अनुच्छेद 163 (1) में कहा गया है कि "राज्यपाल को उसके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि वह इस संविधान द्वारा या इसके तहत है। अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से करने की आवश्यकता है।" उसी अनुच्छेद के खंड 2 में आगे कहा गया है, "यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई मामला है या नहीं, जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, राज्यपाल का निर्णय अपने विवेक से अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी बात की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उसे अपने विवेक से काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।" इस प्रकार, संविधान राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को इतने शब्दों में परिभाषित नहीं करता है। वास्तव में, अपने विवेक का निर्णय लेने की शक्ति स्वयं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यपाल के पास राज्य के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियां हैं
(i) मुख्यमंत्री की नियुक्ति; (ii) मंत्रालय की बर्खास्तगी; (iii) विधानमंडल का विघटन;(iv) सलाह देने, चेतावनी देने और सुझाव देने का अधिकार; (v) किसी विधेयक की स्वीकृति रोकना।
1967 के बाद राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां एक मुद्दा बन गईं, जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता के एकाधिकार को तोड़ा गया और कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आईं। यह घटना जारी है और अलग केंद्र और राज्यों में पार्टियां या पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आ गया है। अब हम 1967 के बाद बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अध्ययन करते हैं।

मुख्यमंत्री का चयन

ऐसी स्थिति में जहां राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ एक राजनीतिक दल रहता है, राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का कोई विवेक नहीं है। उसे बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करना होता है। लेकिन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक व्यक्ति को आपराधिक अपराध में दोषी ठहराया गया है और दो साल से कम की सजा दी गयी है, मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, भले ही वह विधानसभा में बहुमत का समर्थन कर रहा हो। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल श्रीमती फातिम बीवी द्वारा सुश्री जयललिता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा, या अन्यथा, "राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो संविधान और कानूनों के विपरीत हो।" यदि किसी दल को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, तो राज्यपाल के पास पर्याप्त विवेक होता है और अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करता है, ऐसे मामले में, हमेशा विवाद पैदा होता है। यह बताया गया है कि विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी के केंद्र के समान होने की स्थिति में, राज्यपालों ने अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि इस सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया गया था जब एक अलग पार्टी को विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त था, उदाहरण के लिए 1957 और 1965 में केरल, 1971 में पश्चिम बंगाल, 1982 में हरियाणा और यू.पी. 1995 में। गठबंधन के मामले में भी, राज्यपाल ने केंद्र में सत्ता में पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। उदाहरण के लिए 1967 में राजस्थान में राज्यपाल ने संयुक्त विधायक दल के नेता लक्ष्मण सिंह गिल को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित नहीं किया, हालांकि उन्होंने राज्य विधानसभा में बहुमत के समर्थन का दावा किया था।

ऐसे मामले भी आए हैं जहां राज्यपाल द्वारा अल्पमत सरकार स्थापित की गई थी। उदाहरण के लिए 1984 में, आंध्र प्रदेश में भास्कर राव और 1992 में, असम में केशव चंद्र गोगोई और 1988 में तमिलनाडु में श्रीमती रामचंद्रन को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया गया था, हालांकि उन्हें विधानसभा में बहुमत का समर्थन नहीं मिला था। जब राज्यपाल किसी व्यक्ति को त्रिशंकु विधायिका में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, तो वह उन्हें विधान सभा का सामना करने का समय भी देता है। हालाँकि, दिया गया समय विशेष राज्यपाल के निर्णय के आधार पर भिन्न होता है। 1979 में, असम में राज्यपाल ने नियुक्त मुख्यमंत्री जोगिंदर नाथ हजारिका को उचित समय के भीतर विधानसभा का सामना करने के लिए कहा। उसी राज्यपाल ने केशव चंद्र गोगोई को अपना पद ग्रहण करने की तारीख से छह सप्ताह का समय दिया। 1984 में जी.एम. शाह और भास्कर राव को क्रमशः जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में एक महीने का समय दिया गया था। तमिलनाडु में श्रीमती रामचंद्रन को 1988 में विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया था। यूपी में, 1997 में राज्यपाल रोमेश भंडारी ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के शब्दों में, बसपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद बहुमत साबित करने के लिए "सिर्फ दो रात और एक दिन" दिया। कल्याण सिंह ने विरोध किया कि उन्हें आवंटित समय सबसे कम था लेकिन इससे राज्यपाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी राज्यपाल ने 1998 में जगदंबिका पाल को पहली बार में तीन दिन का समय दिया लेकिन बाद में बहुमत साबित करने के लिए तीन दिन और बढ़ा दिए।[5]

मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी

सामान्य संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, एक मुख्यमंत्री जिसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, उसे बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि भारत में इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया है। 1959 में, केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बहुमत का समर्थन होने के बावजूद बर्खास्त कर दिया गया था। इसी तरह, 1987 में एस.एस. बरनाला (पंजाब), 1985 में फारूक अब्दुल्ला (जम्मू और कश्मीर) के मामलों में, एन.टी. 1984 में रामा राव (एपी) और 1989 में बोम्मई (कर्नाटक) में, मुख्यमंत्रियों को तब भी बर्खास्त कर दिया गया जब वे विधानसभा का सामना करने के लिए तैयार थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद एन.टी. रामाराव अपने 163 समर्थकों को राष्ट्रपति के सामने परेड कराने तक की हद तक चले गए। अभी भी ऐसे मामले हैं जब मुख्यमंत्रियों ने दलबदल के कारण बहुमत का समर्थन खो दिया था और राज्यपाल ने न तो उन्हें बर्खास्त किया और न ही बहुमत के समर्थन का परीक्षण करने के लिए विधानसभा

को जल्द से जल्द बुलाने पर जोर दिया। यूपी में ये हुआ था जब मुख्यमंत्री सी.बी. गुप्ता ने बहुमत का समर्थन खो दिया और बहुमत के समर्थन का परीक्षण करने के लिए विधानसभा के शीघ्र सत्र की मांग की गई, तो राज्यपाल ने यह कहकर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि जब कोई "बहुमत खो देता है तो उसे इसे खोजने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।" इसी तरह का रवैया संबंधित राज्यपालों द्वारा 1967 और 1970 में बिहार में, 1971 में पंजाब और बिहार में, 1973 में उड़ीसा में और 1981 और 1982 में असम में अपनाया गया था। कभी-कभी, एक ही राज्यपाल ने एक ही स्थिति में अलग-अलग पदों पर कार्य किया है। उदाहरण के लिए, गोपाल रेड्डी ने 1969 में सीबी गुप्ता को दो महीने से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने की अनुमति दी, लेकिन 1970 में वे तीन दिनों तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे जब विधानसभा की बैठक होनी थी और मुख्यमंत्री चरण सिंह विधानसभा का सामना करने के लिए तैयार थे। .

सरकारिया आयोग ने एक मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें दीं।

1. राज्यपाल को विधानसभा के बाहर अपने दम पर बहुमत के समर्थन के मुद्दे को निर्धारित करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर किया जाना चाहिए।
2. राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक कि वे विधान सभा में बहुमत प्राप्त करना जारी रखते हैं। इसके विपरीत यदि वे बहुमत खो देते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह उन्हें बर्खास्त करने के लिए बाध्य हैं।
3. जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो, तो बहुमत के प्रश्न को सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए।
4. यदि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है, तो उन्हें "संवैधानिक औचित्य के मामले में" उन्हें खारिज नहीं करना चाहिए। वह मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द विधानसभा बुलाने की सलाह दें ताकि बहुमत की परीक्षा हो सके।[6]

आम तौर पर विधानसभा को बुलाने के लिए 30 दिनों की अवधि की अनुमति दी जाती है, जब तक कि बजट पारित करने जैसा कोई बहुत जरूरी काम न हो, जिसमें कम अवधि की अनुमति दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में, अवधि 60 दिनों तक जा सकती है।

विधानसभा को बुलाना और सत्रावसान करना

राज्यपाल के विवेक का एक अन्य क्षेत्र जिसने बहुत विवाद पैदा किया, वह है विधानसभा को बुलाने और सत्रावसान करने की उसकी शक्ति। समय-समय पर सदन को आहूत करना राज्यपाल का कर्तव्य है। केवल संवैधानिक सीमा यह है कि पिछले सत्र के अंतिम दिन और अगले सत्र के पहले दिन के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आम तौर पर, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा को बुलाया जाता है। आमतौर पर राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कार्य करता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बहुमत का समर्थन खो चुके हैं और परिणामस्वरूप विधानसभा का प्रारंभिक सत्र बुलाने के लिए अनिच्छुक हैं, तो यह एक असामान्य स्थिति बन जाती है और राज्यपालों ने विरोधाभासी तरीके से व्यवहार किया है जैसा कि ऊपर देखा गया है। लेकिन यहां जो उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, वह यह है कि कुछ राज्यपालों ने सामान्य प्रक्रिया से हटकर विधानसभा का सत्रावसान किया ताकि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रालय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सके। यह के.सी. 1968 में मध्य प्रदेश में रेड्डी, 1970 में जम्मू-कश्मीर में भगवान सहाय, 1973 में उड़ीसा में बी. डी. जत्ती और 1981 में असम में एल.पी. सिंह। आखिरी मामला ज्यादा दिलचस्प है। अनवरा तैमूर की सरकार विनियोग विधेयक पर एक कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सदन के पटल पर हार गई थी, जिसका अर्थ था कि सरकार ने विधानसभा का विश्वास खो दिया था। एलपी सिंह ने न तो अनवारा तैमूर से इस्तीफा देने का अनुरोध किया और न ही उन्हें बर्खास्त किया। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने विधानसभा का सत्रावसान किया और मंत्रालय को बचाने के लिए खर्च को अधिकृत करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया।[7]

सरकारिया आयोग ने राज्य विधानसभा को बुलाने और सत्रावसान करने के मामले में राज्यपाल के विवेक के प्रयोग के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए:

1. जब तक मंत्रिपरिषद को विधान सभा का विश्वास प्राप्त है, विधानमंडल के एक सदन को बुलाने और सत्रावसान करने और विधान सभा को भंग करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की सलाह, यदि ऐसी सलाह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक नहीं है, राज्यपाल पर बाध्यकारी होना चाहिए।
2. कुछ स्थितियों में, राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग केवल विधानसभा को बुलाने के लिए कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में जिम्मेदार सरकार की प्रणाली संविधान में परिकल्पित मानदंडों के अनुसार काम करती है।
3. यदि मुख्यमंत्री छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर विधानसभा को बुलाने की सलाह नहीं देता है, तो राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर विधानसभा को बुला सकता है।

4. यदि मुख्यमंत्री अपने कार्यभार संभालने के 30 या 60 दिनों के भीतर विधानसभा को नहीं बुलाता है और राज्यपाल को लगता है कि वह अब विधानसभा के विश्वास का आनंद नहीं ले रहा है, तो वह बहुमत के समर्थन की परीक्षा आयोजित करने के लिए विधानसभा को बुला सकता है।

राज्य विधानसभा का विघटन

एक अन्य क्षेत्र जहां राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है, वह राज्य विधानसभा के विघटन के संबंध में है। यहां भी संसदीय लोकतंत्र का मानदंड मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से इस शक्ति का प्रयोग करना है। हालाँकि, यदि किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है, तो राज्यपाल के पास ऐसी सलाह को स्वीकार नहीं करने का विवेक है और वह वैकल्पिक सरकार के लिए प्रयास कर सकता है। इस प्रकार हरियाणा में राव बीरेंद्र सिंह, 1967 में पंजाब में गुरनाम सिंह और 1971 में गुजरात में हितेंद्र देसाई की विधानसभाओं को भंग करने की सलाह को खारिज कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर, 1970 में केरल में, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार में 1971 में, संबंधित मुख्यमंत्रियों की सिफारिश पर विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था, हालांकि विभिन्न राज्यपालों के दृष्टिकोण में कोई समान दृष्टिकोण नहीं रहा है।
सरकारिया आयोग ने इस संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें दीं:

1. यदि मुख्यमंत्री को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तो राज्यपाल को विघटन की सलाह को स्वीकार करना चाहिए।
2. जब एक मुख्यमंत्री जो या तो हार गया हो या बहुमत का समर्थन खो दिया हो, राज्यपाल को एक वैकल्पिक सरकार के लिए प्रयास करना चाहिए। वह इस उद्देश्य के लिए विधानसभा को भी बुला सकता है।
3. यदि अंततः एक व्यवहार्य मंत्रालय उभरने में विफल रहता है, तो राज्यपाल को संबंधित राजनीतिक दलों के नेताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श करने के बाद विधानसभा को भंग करने और नए चुनावों की व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए।

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए राज्यपाल की सिफारिश के संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहां राज्यपाल को पूरी तरह से अपने विवेक पर कार्य करना है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करना है। हालाँकि, राज्यपाल का कार्यालय इस शक्ति के उपयोग पर गंभीर विवाद का केंद्र बन गया है, बहुत बार इसका पक्षपातपूर्ण हितों के लिए दुरुपयोग किया गया है।

अन्य विवेकाधीन शक्तियां

उपरोक्त के अलावा राज्यपाल की अन्य विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जो इस प्रकार हैं:
अनुच्छेद 356* के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हुए राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्य में विपक्षी दल या गठबंधन को सरकार बनाने से रोकने के लिए केंद्र में सत्ताधारी दल के हित में राज्यपाल द्वारा इस शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग किया गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान, हालांकि एक सलाहकार नियुक्त किया जाता है

1. राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को सलाह देने के लिए, वह वास्तव में राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है।
2. राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। वह इसे राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है।
3. गठबंधन सरकार के मामले में राज्यपाल ने कई मामलों में मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया है।

सरकारिया आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के बार-बार दुरुपयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसलिए सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का उपयोग "बहुत कम" ... अंतिम उपाय के रूप में किया जाए" त्रुटिपूर्ण राज्य सरकार को उचित चेतावनी के बाद। जब ऐसा किया जाता है , राज्यपाल की रिपोर्ट एक "बोलने वाला दस्तावेज" होना चाहिए जिसमें "सभी भौतिक तथ्यों और आधारों का एक सटीक और स्पष्ट विवरण हो। .." दुर्भावना के आधार पर न्यायिक समीक्षा के उपाय को थोड़ा और सार्थक बनाने के लिए आयोग का सुझाव है कि उद्घोषणा में भौतिक तथ्यों और आधारों को रखा जाना चाहिए जिसे व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह कहता है कि संसद की अनुमति के बिना विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

संविधान के लागू होने के पश्चात से राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन करना।
To study the role of Governor after enforcement of our Constitution.

निष्कर्ष

दुर्भाग्य से ये सभी सुझाव कागजों पर ही रह गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए यह आवश्यक है कि राज्यपाल न केवल सूक्ष्म निष्पक्षता और प्रत्यक्ष निष्पक्षता के साथ कार्य करे बल्कि उसे इस रूप में भी देखा जाए। दूसरे शब्दों में राज्यपाल की भूमिका केवल एक अंपायर की नहीं होनी चाहिए जो यह देखता है कि खेल नियमों के अनुसार खेला गया है बल्कि यह भी देखना चाहिए कि यह सही भावना से खेला जाता है। और यह सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करके संभव बनाया जा सकता है, हालांकि कुछ पर्यवेक्षक और राजनीतिक दल इन्हें पर्याप्त नहीं पाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा स्वस्थ परंपराओं का विकास भी आवश्यक है, ताकि अधिक लोकतांत्रिक वातावरण के साथ राज्य सरकार के कामकाज में राज्यपाल की भूमिका अधिक सकारात्मक हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Gupta D.C., Indian Government and Politics 1991, New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. अनुवाद स्वयं*
2. *Sharan, P., Government and Politics of India, Recent Developments, 1986, New Delhi, Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd. अनुवादस्वयं*
3. *Singh M.P., V.N. Sukla's Constitution of India, 2001, Lucknow, Eastern Book Company Lucknow. अनुवादस्वयं*
4. *H.A. Gani, Centre-State Relations and Sarkaria Commission, New Delhi, Deep and Deep, 1990, p. 31 अनुवादस्वयं.*
5. *अवस्थी भारत शासन एवं राजनीति शिवलाल अग्रवाल पब्लिकेशन आऐगरा*
6. *Narang A.S. Indian Government and Politics Gitanjali Publication New Delhi अनुवादस्वयं*
7. *Role of the Governor and Multiparty System Saturday 1 March 2008, by Indrajeet Singh अनुवाद स्वयं अनुवादस्वयं*